फरीदाबाद के इकलौते टाउन पार्क की बदहाली

फरीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 12 स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के इकलौते टाउन पार्क में जहां लाखों रुपए वेतन के रूप में अधिकारियों और कर्मचारियों व ठेकेदारों को इसकी देखभाल के रूप में प्रतिमाह दिया जा रहा है। इसके बावजूद वहां की हालत बेहद खस्ता है। चारों ओर की ग्रिल जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है जिससे आने-जाने के अवैध रास्ते खुले होने के कारण आवारा पशु, कुत्ते, गाय व बैल इत्यादि वहां दिनभर घूमते रहते हैं। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर पार्क के अंदर चारों ओर व बाहर कूड़ा-कचरा, गंदगी, प्लास्टिक इत्यादि के ढेर लगे हुए हैं। पार्क के कुछ हिस्सों में लगातार पानी बहने से जहां एक ओर दलदल बनी हुई है।

वहीं बहुत से हिस्से पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं। वहां की वनस्पति, पेड़-पौधे, घास इत्यादि भी इस कारण निर्जीव होते जा रहे हैं। आई लव फरीदाबाद पॉइंट पर रौशनी देने वाली लाइटें बंद पड़ी है। वहीं इसके दूसरी ओर विशेष रूप से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी द्वारा बनाए गए नवनिर्मित पक्षी घर की लाइटों का बिजली कनेक्शन ही नहीं जोड़ा गया। जानबूझकर केवल एक-एक नट पर उन लाइटों को फिट कर दिया गया है ताकि कोई भी चोर आसानी से उन्हें खोल कर ले जा सके।

शहर निवासियों व पार्क में घूमने आने वाले लोगों के लिए लाखों रुपए की लागत से लगाया गया म्यूजिक सिस्टम अक्सर बंद रहता है। उद्यान एवं बागवानी विभाग के साथ-साथ एचएसवीपी का इलेक्ट्रिकल विंग भी पूरी तरह से ऐसी लापरवाही लगातार शिकायत किए जाने व समय-समय पर विधायक जी द्वारा स्वयं निरीक्षण व निर्देश दिए जाने के बावजूद बरत रहा है। यहां अब तक कागजों में शायद लाखों पेड़ लगा दिए गए हैं और उनकी देखभाल पर भी उतनी ही संख्या के अनुसार ठेकेदारों को पेमेंट की जा रही है। लेकिन मौके पर सैकड़ों पेड़ों में दीमक लग चुकी है और दर्जनों पेड़ सूख कर गिर चुके हैं। लेकिन इसकी जिम्मेवारी तय नहीं की जा रही और भविष्य में ऐसा ना हो इसके भी इंतजाम नहीं किए गए। इस पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए सरकारी झूलों की हालत भी खस्ता है। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के नाम पर इसी पार्क में बनाए जाने वाले पुस्तकालय का निर्माण कार्य पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अधर में लटका हुआ है।

ईएसआई कॉर्पोरेशन के अपने ही स्टाफ़ में आधे पद रिक्त पड़े हैं

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

देश भर के करीब साढे तीन करोड़ मज़दूरों से उनके वेतन का चार प्रतिशत वसूल कर डेढ लाख करोड़ के खजाने पर कुण्डली मारे बैठे कॉर्पोरेशन में कुल स्वीकृत पदों के करीब आधे पद खाली पड़े हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि जिस संस्थान में काम करने वाले ही पूरे न हों तो वह संस्थान उन मज़दूरों को क्या सेवायें दे पायेगा जिनसे नियमित वसूली करने में वह कभी नहीं चूकता।

31 मार्च 2022 को कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कार्पोरेशन में कुल 20494 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 9246 पद रिक्त हैं। गौरतलब है कि ये स्वीकृत पद जब बनाये गये थे तब बीमाकृत मज़दूरों की कुल संख्या मात्र डेढ करोड़ थी जो आज बढ़कर साढे तीन करोड़ हो गई है। इस हिसाब से तो स्वीकृत पदों की संख्या बढनी चाहिये थी लेकिन यहां तो पहले से ही स्वीकृत पद भी भरे नहीं जा रहे।

कार्पोरेशन की विभिन्न श्रेणियों के पदों का ब्योरा इस प्रकार है:

	पद	रिक्त
एलडीसी	1908	784
एमटीएस	3514	2622
यूडीसी	6523	306
असिस्टेंट	3612	740
एसएसओ	2464	595
एडी	413	216
डीडी	407	205
सीनियर डीडी	180	180

किसी भी संस्थान को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पदों को सर्जित किया जाता है। समझा जा सकता है, जब इन पदों पर लोग होंगे ही नहीं तो काम कैसे चल पायेगा। बताने की जरूरत नहीं कि निगम के पास मजदूरों का दिया हुआ भारी भरकम खजाना पड़ा हुआ है उसके बावजूद पदों को खाली रखा जा रहा है। पदों के खाली रहने से काम सुचारू रूप नहीं चल सकता और जब काम ही नहीं चलेगा तो इसका दुष्प्रभाव उन सभी मजदूरों पर पड़ना स्वभाविक है जिनके लिए यह कार्पोरेशन बनाया गया है। उदाहरण के लिए फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में 300 से अधिक इस तरह के (दफ्तरी) पद खाली पड़े हुए हैं। इसके चलते इन पदों पर उन लोगों से काम लिया जा रहा है जो सीधे तौर पर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े होते हैं।

राज्य की समस्त मेडिकल जमात सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है

मेडिकल छात्रों से 300 करोड़ कमाने के चक्कर में फंस गये खट्टर

फ़रीदाबाद (म.मो.) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्व सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर अपनी किताब 'द बंच ऑफ थॉट्स' में लिख गये हैं कि धन सब लोगों के पास नहीं रहना चाहिये, इसे केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों के पास ही रहना चाहिये। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए तमाम भाजपाई सरकारें देश की जनता से अधिकाधिक धन निचोड़ने के नये-नये उपाय खोजते रहते हैं। इसी खोज के दौरान खट्टर जी ने चिकित्सा छात्रों से भी सालाना 300 करोड़ रुपये निचोड़ने का 'नायाब' फार्मूला खोज निकाला।

संघ द्वारा प्रशिक्षित एवं दीक्षित मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनकर, राज-काज चलाने के लिये अपने ही जैसे संघ प्रशिक्षित सलाहकारों की एक अच्छी-खासी पलटन अपने चारों ओर जुटा रखी है। ऐसे ही सलाहकारों की सलाह पर चलते हुए खट्टर महाशय न केवल चिकित्सा छात्रों बल्कि पूरे चिकित्सा समाज के जाल में ऐसे जा फंसे हैं जिससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता अब सूझ नहीं रहा है। राज्य भर के तमाम (यूजी व पीजी) छात्र तो खट्टर के इस फैसले के विरोध में डटे ही हैं, साथ में पूरा डॉक्टर समाज भी उनके समर्थन में आ जुटा है। और तो और हरियाणा सरकार के डॉक्टरों के संगठन ने भी उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है।

मजे की बात तो यह है कि तमाम विरोधी राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठन तो इनका समर्थन कर ही रहे हैं, संघ एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की भी हिम्मत इनके सामने पस्त है। रोहतक-करनाल जैसे शहरों में जहां भाजपाईयों का अच्छा-खासा जमावड़ा है, विधायक एवं सांसद भी इन्हीं के हैं, इसके बावजूद खट्टर के समर्थन में मुंह खोलने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में सरकार का कोई भी आदेश केवल तभी शिरे चढ़ सकता है जब उसे जन-समर्थन हासिल हो। इसी जन-समर्थन के अभाव में फंस कर खड़े खट्टर अब अपने अफसरों पर दोष मढ़ रहे हैं कि उन्हें छात्रों को समझाना नहीं आया। मान लिया कि उच्च शिक्षित यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी तो नालायक हैं, लेकिन संघ द्वारा प्रशिक्षित खट्टर अपनी लियाकत का इस्तेमाल उन्हें समझाने के लिये क्यों नहीं करते?

बीते आठ साल से, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का झुनझुना बजाने वाले खट्टर अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं कर पाये हैं। अब वे कहने लगे हैं कि 13-14 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिये उन्हें 16-17 हजार करोड़ रुपये चाहिये। इस रकम के लिये ही तो वे प्रत्येक मेडिकल छात्र से 10 लाख वार्षिक की फ़ीस वसूलेंगे। खट्टर जी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बीते आठ साल में आप दो लाख करोड़ से अधिक का कर्जा लेकर घी पी चुके हैं। वर्ष 2014 में जब खट्टर मुख्यमंत्री बने तो राज्य पर कुल 89 हजार करोड़ कर्जा था जो आज बढ़कर पौने तीन लाख लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) के अनुसार जीडीपी का पांच प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना चाहिये। इसके विपरीत भारत में कुल जीडीपी का मात्र एक प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। संदर्भवश, भारत की जीडीपी 28 अरब रुपये की है। इसका केवल एक प्रतिशत यानी कि कुल 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये, केन्द्र तथा समस्त राज्य सरकारों द्वारा खर्च किये जाते हैं। पिछले लगभग 14 वर्षों से इस एक प्रतिशत को बढ़ा कर तीन प्रतिशत किये जाने का एलान तो होता रहा है लेकिन वास्तविकता तो जहां की तहां ही रही। हां, ड्रामेबाजी के तौर पर कांग्रेस सरकार ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' तथा मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' जैसे झुनझुने जनता के हाथ में थमा दिये। खट्टर सरकार इससे भी आगे बढ़कर, चिकित्सा सेवाओं का वास्तविक विस्तार करने की अपेक्षा 'टेलीमेडिसिन' जैसे सगूफों से जनता को बहला रही है।

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मिल कर चिकित्सा सेवाओं पर कुल 2 लाख 80 हजार करोड़ खर्च किया जाता है। इसमें से 90 हजार करोड़ केन्द्र तथा शेष 1 लाख 90 हजार करोड़ तमाम राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाता है। इस कुल खर्च का करीब तीन गुणा यानी 8 लाख 40 हजार करोड़ जनता द्वारा प्राइवेट माध्यमों के जरिये खर्च किया जाता है। इसमें वह रकम भी शामिल है जो ईएसआई कॉर्पोरेशन मज़दूरों से वसूल करके चिकित्सा सेवाओं पर खर्च करती है।

इस वर्ष का हरियाणा सरकार का कुल बजट 1 लाख 42 हजार करोड़ का है। इसमें से चिकित्सा सेवाओं एवं चिकित्सा शिक्षा के लिये मात्र 7 हजार 126 करोड़ रुपये रखा गया है जो इन सेवाओं के लिये बहुत ही कम है। इस कमी के चलते राज्य सरकार के सभी चार कॉलेज तो दुर्दशा का शिकार हैं ही और पांचवा (छांयसे वाला) भाग्य के भरोसे खड़ा है। तमाम तरह की फिजूल खर्चियों तथा तरह-तरह के घोटालों एवं अय्याशियों के लिये सरकारी बजट में कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल चिकित्सा सेवाओं के लिये। राज्य के मंत्री-संत्री जहां लाखों रुपये का तेल अपनी सरकारी कारों में फूंक डालते हैं वहीं खट्टर ने सरकारी हेलिकॉप्टर को झोटा-बुग्गी बना रखा है जिसे लेकर वे आये दिन दिल्ली, फ़रीदाबाद, गुड़गांव आदि शहरों में टहलने आ जाते हैं।

डाक्टर आरएस गौड़ का पेट वेतन से नहीं भरता, एमआरआई का कमीशन भी चाहिए

फरीदाबाद (म.मो.) बीके अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार और यहाँ के अधिकारी व अन्य स्टाफ द्वारा अस्पताल में इलाज कराने आये मरीजों के प्रति हो रही लापरवाही की पोल मजदूर मोर्चा खोलता आ रहा है। इसके बावजूद इन लोगों में सुई बराबर भी सुधार नहीं आया, अब तक तो इस अस्पताल में आने वाले मरीजों को दलाल ही घेरा करते थे, लेकिन अब तो डॉक्टर भी इसी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला।

दिनांक 14 नवम्बर मंगलवार को राज मिस्त्री का काम करने वाले मोहम्मद रफ़ी अनखीर गांव पुलिस चौकी से बड़खल कि ओर जाने वाली रोड की तरफ अपनी बाइक से जा रहे थे। अचानक रास्ते में आवारा सांड से टकराकर घायल हो गए। जैसे तैसे करके ये लोग करीब सुबह 11 बजे बीके अस्पताल के आपातकालीन विभाग में पहुंचे, वहां पट्टी बाँध कर अग्रिम जांच के लिए रूम नंबर 19 में हड्डी विशेषज्ञ के पास भेज दिया।

मोहम्मद रफी को लेकर भटकते परिजन

डॉ. गौड़ : बिना सेवा के खाते मेवा

वहां डाक्टर आरएस गौड़ ने उन्हें एमआरआई जांच के लिए अजरौंदा मोड़ स्थित फोकस लैब पर यह कहते हुए भेज दिया कि उनके यहाँ के एमआरआई की रिपोर्ट अच्छी नहीं आती। डाक्टर गौड़ ने मरीज को यह भी कहा की लैब वाले को मेरा नाम बता देना। लैब वाले ने चंगुल में आये शिकार से कहा की वैसे तो रेट 8000 का है लेकिन डॉक्टर की सिफारिश के चलते 4000 में हो जाएगा, हो भी गया।

जबकि यही काम बिना किसी सिफारिश के बीके में ही 2800 रूपए में होता है। रिपोर्ट लेकर रफ़ी के परिजन डाक्टर गौड़ के पास पहुचे तो डाक्टर ने रिपोर्ट तो ओके कर दी, लेकिन इलाज के लिए डाक्टर के साथ सौदेबाजी में जब मामला नहीं जमा तो परिजन मरीज को अन्यत्र किसी निजी अस्पताल में ले गए। समझा जा रहा है कि इस बीच परिजनों की भेंट किसी निजी अस्पताल के दलाल से हो गई थी जो उन्हें डाक्टर गौड़ से सस्ता पड़ रहा था।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।